1970 together with an explanatory memorandum.

(vii) G. S. R. 1792 (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated the 17th October, 1970 together with an explanatory memorandum.

(viii) G. S. R. 2362 (Hindi version) published in Gazette of India dated the 5th September, 1970 together with an explanatory memorandum.

[*Placed in Library. See* No. LT—4331/70]

NOTIFICATIONS UNDER THE MERCHANT SHIPPING ACT, AND THE MOTOR VEHICLES ACT

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI IQBAL SINGH): I beg to lay on the Table—

(1) A copy of the Merchant Shipping (Certificate of Service) Rules, 1970 (Hindi and English versions) published in Notification No. G. S. R. 1682 in Gazette of India dated the 19th September, 1970, under sub-section (3) of section 458 of the Merchant Shipping Act, 1958. [*Placed in Library. See* No LT—4333/70]

(2) A copy of the Punjab Motor Vehicles (Chandigarh Amendment) Rules, 1970 (Hindi and English versions) published in Notification No. 5061-HII (2)—70/7687 in Chandigarh Gazette dated the 1st May, 1970, under sub-section (3) of section 133 of the Motor Vehicles Act, 1939. [*Placed in Library. See* No. LT—4334/70]

(3) A statement showing reasons for delay in laying the Notification mentioned at (2) above. [*Placed in Library. See* No. LT—4335/70]

PETITION RE: PREVENTION OF FOOD ADULTERATION ACT

SHRI K. P. SINGH DEO (Dhenkanal): I present a petition signed by Shri Daitary, Sahu President, Banika Sangha, Dhenkanal (Orissa) on behalf of 151 others regarding the prevention of Food Adulteration Act, 1954.

12.41 hrs.

BUSINESS OF THE HOUSE

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, AND SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI RAGHU RAMAIAH): With your permission, Sir, I rise to announce that Government Business in this House during the week commencing from 23rd November, 1970 will consist of:—

1. Further consideration and passing of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Bill, 1967, as reported by the Joint Committee.

2. Discussion on the Resolution seeking disapproval of the Foreign Exchange Regulation (Amendment) Ordinance, 1970 and consideration and passing of the Foreign Exchange Regulation (Amendment) Bill, 1970.

3. Consideration and passing of:

   (i) The Architects Bill, 1970, as passed by Rajya Sabha.

   (ii) The Salaries and Allowances of Officers of Parliament (Amendment) Bill, 1970.

   (iii) The Tea Districts Emigrant Labour (Repeal) Bill, 1967.

   (iv) The Indian Medicine Central Council Bill, 1970, as passed by Rajya Sabha.

   (v) The Supreme Court Judges (Conditions of Service) Amendment Bill, 1968.

   (vi) The Chartered Accountants (Amendment) Bill, 1969.

   (vii) The Maternity Benefit (Amendment) Bill, 1967, as passed by Rajya Sabha.

[Shri Raghu Ramaiah]

(viii) The Industrial Disputes (Amendment) Bill, 1968, as passed by Rajya Sabha.

4. Further discussion under Rule 193 regarding shortage of fish supply in West Bengal, at 4 p. m. on Thursday, the 26th November, 1970.

Some hon. Members rose—

MR. SPEAKER : The other day I requested hon. Members not to make it a debating hour. Those who want to raise certain discussions should send their suggestions to the Business Advisory Committee and only if the Business Advisory Committee has not accepted it they can ask about it in the House. I am happy that Mr. Banerjee sent this information in writing. I thought I should send it to the BAC and let him know later on ; none else had come.

SHRI S. M. BANERJEEE (Kanpur) : I should make my position clear. I sent that note because if I rise I seem to injure your sentiments which I do not want to do.

MR. SPEAKER : There are no sentiments at all ; it is only a question of rules and procedure. If you are within them, anything is all right.

SHRI S. M. BANERJEE : According to rules we are allowed to put questions.

SHRI BAL RAJ MADHOK (South Delhi) : We would have agreed to the suggestion that the matter should be refereed to the Business Advisory Committee. But we find that even when the thing had been adopted by the BAC it never comes before the House ; that has been our experience in the last two or three sessions.

The municipal elections of Delhi Corporation are due in March but Mr. Pant has announced that the Government was re-thinking about the new set-up of Delhi ; in that case the Corporation might be dissolved. Whatever decision has to be taken, has been taken before the Corporation elections are held. Otherwise, if the Jan Sangh gets a majority and then you dissolve it, this will not be tolerated. This is a matter of very urgent importance and immediate steps should be taken ; the whole matter should be discussed in the House as to what future set-up should we have in Delhi.

श्री रवि राय (पुरी) : अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछली बार भी इस सवाल को उठाया था कि डिफेक्शन कमेटी की रिपोर्ट पर बहस होनी चाहिए। हमको लगता है कि मंत्री महोदय भूल ही गये हैं कि इस तरह की रिपोर्ट सदन के सामने आई थी। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय ऐलान करें कि इस सत्र में डिफेक्शन कमेटी की रिपोर्ट पर बहस होगी या नहीं।

दूसरी बात यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर भी सदन में बहस होनी चाहिए। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय इन्टरनेशनल सिचुएशन पर बहस के लिये हमको मौका दें।

श्री स० मो० बनर्जी : मैंने आपकी सेवा में कालिंग अटेंशन नोटिस भेजा था जिसमें कानपुर के 4 हजार सुरक्षा कर्मचारियों को उनके क्वार्टरों से निकाले जाने की बात थी। सुरक्षा मंत्री जो ने आश्वासन दिया था कि उनको वहां से निकाला नहीं जायेगा। मैं चाहता हूं कि इसके बारे में वह बयान दें।

दूसरी बात यह है कि प्रधान मंत्री जी की कोठी के सामने रेलवे कर्मचारी इन्टेरिम रिलीफ के बारे में धरना दे रहे हैं और पार्लियामेंट के मेम्बर भी देंगे। इसके सम्बन्ध में, मैं चाहता हूं प्रधान मंत्री या वित्त मंत्री बयान दें।

तीसरी चीज यह है कि यहां पर बार-बार आश्वासन दिया गया था कि जिन पुलिस वालों के खिलाफ ऐक्शन लिया गया था, जिनको डिसमिस या सस्पेंड किया गया था दिल्ली एजिटेशन में भाग लेने के कारण, उनके मामले पर विचार किया जायेगा। उनके बारे में कुछ फैसला हो चुका है। मैं चाहता हूं कि गृह मंत्री जी इसके बारे में बयान दें ताकि उनकी तकलीफें भी दूर हो जायें।

MR. SPEAKER : I prefer moving from my left to right ; as I keep on moving nobody should get up from the benches which had been finished. I shall start again.

DR. RAM SUBHAG SINGH (Buxar) : You may have seen the statement of Shri Dharam Teja before a magistrate in a London court ; he has made certain sensational disclosures and they pertain to matters about him and the Government. We should like to be acquained by the Government with correect facts....(*Interruptions*)

MR. SPEAKER : Some hon. Members came to me with this motion and I considered it. Teja's name is being confused very much. There was a person who was first Secretary and who was present at the time of Mr. Shastri's death. We do not want to raise a discussion because they are already seized of the matter in court ; our Government is also represented in that case. I shall give an opportunity to the House but at a later stage ; we shall discuss this. It is a very serious and mischievous thing and it has happend. We shall discuss it later on, not now.

श्री कंवरलाल गुप्त (दिल्ली सदर) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी आपसे वही कहना चाहता था जो डा० राम सुभग सिंह ने कहा। इस सम्बन्ध में एक और बात कही गई है कि उन्होंने खुद आफर किया था अगस्त के महीने में, सरकार को चिट्ठी लिखी थी, कि वह यहां आने के लिये तैयार हैं··

अध्यक्ष महोदय : अब वह बात खत्म हो गई।

श्री कंवरलाल गुप्त : मैं जानना चाहता हूं कि यह कहां तक ठीक है कि चिट्ठी आई है। यह एक सीरियस बात है।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : इन दिनों रेलगाड़ियां बहुत विलम्ब से चल रही हैं। मैं चाहूंगा कि इस सदन में रेलगाड़ियों के सिलसिले में कोई बहस हो, जिस रूप में भी वह हो सके। इसके लिये भी सरकार को समय निकालना चाहिये।

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं चार चीजों के बारे में संसद्-कार्य मंत्री से सफाई चाहता हूं :

(1) क्या मंत्री महोदय प्रीवी पर्सेज के बारे में दुबारा कोई नया बिल इस सत्र में पेश करने जा रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय हो, जब तक संविधान में वह धारायें हैं तब तक नैतिक दृष्टि से यह अच्छा नहीं लगता। इसलिए क्या वह प्रीवी पर्सेज के बारे में दुबारा कोई विधेयक पेश करेंगे ?

(2) आपने उस दिन हमसे कहा था कि जिन कम्पनियों ने अनियमित रूप से अपनी शक्ति को बढ़ाया है उसके बारे में इस सदन में चर्चा न हो सकी तो हम किसी दूसरी शक्ल में लेंगे। क्या इसके लिए अगले सप्ताह कोई समय दिया जायेगा ?

(3) मैंने एक नोटिस दिया है व्यापक सवाल बना कर कि राज्य सरकारों के कर्मचारियों की जो तन्ख्वाहें हैं उनको सुधारने के बारे में केन्द्रीय सरकार के द्वारा क्या सहायता की जा सकती है, विशेषकर महाराष्ट्र की हड़ताल के मामले को लेकर। क्या इसके लिये भी समय मिलेगा ?

(4) अन्तिम बात यह है कि आम चुनाव की बात जोरों से चल रही है। तो जो 18 और 21 वर्ष के बीच के युवक और युवतियां हैं उनको वोट का अधिकार दिये जाने वाले विधेयक को भी पास करने की बात क्या वह सोच रहे हैं ?

श्री शिव चन्द्र झा (मधुबनी) : चौथी योजना के लिये पन्द्रह घन्टे रखे गये हैं। जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं उससे लगता है कि आगामी सप्ताह ही नहीं उससे अगले सप्ताह में भी उस पर बहस नहीं हो सकेगी। अखबारों में आया है कि साइज में उसके पन्द्रह परसेंट कट किया गया है और फिर आता है कि उसके

[श्री शिव चन्द्र झा]

साइज को बढ़ाया जा रहा है। इस तरह की आंख मिचौनी चौथी योजना के साथ करना ठीक नहीं है। मैं चाहता हूं कि आगामी में नहीं तो उससे अगले सप्ताह मे अवश्य चौथी योजना पर बहस हो।

श्री टी० विश्वनाथन का बिल कमेटी में गया था। वह छोटा सा विधेयक है। इसके मुताल्लिक उन्होंने भी संसद् कार्य मंत्री महोदय को लिखा है। उसको इसी सत्र में पास किया जाना चाहिये। वह संविधान में संशोधन करने वाला विधेयक है। उसमें अधिक समय नहीं लगेगा। उसको आप सदन में लाकर पारित करें।

प्रिवी पर्स के बारे में भी सरकार स्थिति को साफ करे। उनको समाप्त करने के लिये संविधान में संशोधन करने वाला विधेयक आप ला रहे हैं या नहीं।

तेजा वाली बात भी उठाई गई है। तीन दिन पहले स्टेट्समैन में, संडे स्टेट्समैन में उसके मुताल्लिक आया था, डिसकर्टसी टू तेजा। वह दूसरा तेजा है। उसके मुताल्लिक भी बहस होनी चाहिये।

SHRI HEM BARUA (Mangaldai); Shri Dharma Teja has made certain serious reflections and serious aspersions on the Members of Parliament and the courts of India. Therefore, I would request Government to make a statement clarifying the position in the face of these serious allegations made by Shri Dharma Teja.

MR. SPEAKER: We shall have a discussion on it later on.

SHRI HEM BARUA: Secondly, Government have decided to open a second refinery in the public sector in Assam. There should be a statement on this here, because what we have gathered is from the newspapers only.

Thirdly, we have not discussed the international situation so far. There should be a discussion on the international situation in the House.

MR. SPEAKER: We are having it today.

SHRI J. H. PATEL (Shimoga): I would like to refer to two issues which have been a permanent source of trouble between States in the southern part of our country. I would refer particularly to the Cauvery water dispute between Tamil Nadu and Maysore and the boundary dispute between Maharashtra and Mysore. I would like to know what this Government is going to do to solve these problems. It only knows how to create the problem, but it never comes forward with solutions and therefore those problems become a permanent source of trouble, because these are matters about which the people of those States are very much agitated. Government comes to the resuce of the situation only when something happens there. I would like to know what solution the Government of India is going to put forward before Parliament on these two matters.

श्री रणधीर सिंह (रोहतक): हम इन बैंचों पर क्या बैठ गये, ऐसा मालूम पड़ता है कि एम० पी० ही हम नहीं रहे हैं। हम भी जीत कर आये हैं, एक एक लाख के बहुमत से जीत कर आये हैं। क्या हम आदमी ही नहीं रहे? जब शुरू करते हैं उधर से उधर उलटा चक्कर है, इधर से सीधा चक्कर है।

श्री नाथपाई: इसमें कोई गलतफहमी नहीं है। आप आदमी हैं।

MR. SPEAKER: The hon. Member should have some patience and wait. I am coming from the left to the right, just like the clock.

SHRI S. KUNDU: I would like to raise only one matter. I would request you to ask the hon. Minister of Parliamentary Affairs to raise a discussion in the coming week about the soaring up of prices. This problem was just discussed, and Snri Y. B. Chavan has also agreed to a discussion, and other Members also have agreed that this matter should be discussed. This is cutting down the income of the poor people who have a lower pay packet. The prices are going up at a speed comparable to that of the jets. What happens here is that we give so much emphasis on the law and order problem.

Basic issues are always forgotten. So I would request that this very important issue is taken up and something is done about it. Un-

less the basic problems are discussed here, this Lok Sabha will not be able to fulfil the aspirations of the people.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (हापुड़) : मुझे दो बातें कहनी हैं। गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री मिर्धा ने पीछे एक वक्तव्य दिया था और बताया था कि श्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के सम्बन्ध में अधिकारियों के वक्तव्य नहीं बदले जा रहे हैं और जल्दी ही उनको सभा पटल पर रखा जायगा। लेकिन सरकार उनको सभा पटल पर नहीं रख रही है। इससे तरह तरह के सन्देह पैदा हो रहे हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार जल्दी से सारे कागजात सभा पटल पर रखे और उसके ऊपर इस सदन में चर्चा के लिये समय दिया जाए।

दूसरी बात मैं आकाशवाणी की निष्पक्षता के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। समाचारों के प्रसारण के सम्बन्ध में कल राज्य सभा में बहुत बड़ा हंगामा हो कर चुका है। लोक सभा में ऐसी स्थिति न आए इसके लिए यह आवश्यक है कि आप प्रयत्न करें कि चर्चा से पहले ही कोई निष्पक्ष जांच समिति बैठ जाए ताकि आकाशवाणी जोकि जनता की सम्पति है उसका उपयोग किसी दल विशेष के लिये न हो सके।

श्री रणधीर सिंह : चंडीगढ़ के फैसले के मातहत फाजिल्का तथा अबोहर हरियाणा को दिया गया था। मेरे पास हर रोज एक मन डाक पहुंच जाती है कि वहां पूरा पानी नहीं दिया जाता है, पूरी बिजली नहीं दी जाती है, डिवेलेपमेंट खत्म हो गया है, एजुकेशन की फैसिलिटीज भी नहीं दी जा रही हैं। इन इलाकों को मिलते अभी साल डेढ या दो साल लग सकते हैं। मैं चाहता हूं कि कम से कम इस अर्से तक इस इलाके को सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड एरिया बना दिया जाये और बाद में इसको हम को दे दिया जाए। क्या इसके बारे में आप कुछ कहेंगे ?

जमीन पर सीलिंग, फार्मज पर सीलिंग, देहातों पर सीलिंग की बात हर रोज होती है लेकिन ये जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, टाटा बिड़ला, डालमिया हैं, और बड़ी बड़ी अर्बन प्रापर्टी के मालिक हैं, उन पर सीलिंग की बात कोई नहीं करता है। क्यों नहीं उन पर सीलिंग लगाई जाती है। क्या गरीब मछलियों को ही पकड़ा जायगा और मगर मच्छों को पकड़ा नहीं जायेगा ? अर्बन प्रापर्टी पर सीलिंग के बारे में सरकार का क्या कहना है।

क्रशिंग सीजन आ गया है केन का। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब इत्यादि में जो करोड़ों रुपया केन के मालिकों का मिल मालिकों की तरफ बकाया है, वह तो उनको दिलाया जाये। और साथ ही साथ आगे ठीक कीमत उनको दिलाने की व्यवस्था की जाये। ऐसा किया जाएगा या नहीं ? क्या आप एश्योरेंस देंगे कि आगे किसानों की इस तरह से शामत नहीं आयेगी।

पचास बार दिल्ली पुलिस वालों के बारे में कहा जा चुका है। उन बेचारों ने क्या जुर्म किया है ? लगातार दो साल से उनको झांसा दिया जा रहा है, कोई उनको पूछता ही नहीं है। मैं सोचता था कि प्रधान मंत्री जब होम मिनिस्टर बनी तभी इनको बहाल कर दिया जायेगा। इन्होंने क्या जुर्म किया है। सेंट्रल एम्प्लाईज आपने लाखों की तादाद में बहाल कर दिये। इन्होंने क्या इतना भारी जुर्म किया है कि आप इनकी बात सुनते ही नहीं हैं। उनको आप बहाल करें। बीस रुपये जो उनको तनख्वाह के तौर पर मिलते हैं, उससे कैसे उनका काम चलेगा ?

MR. SPEAKER : Only suggestions in brief; no arguments in support or debate thereof.

SHRI AMRIT NAHATA (Barmer) : I want to raise three issues. First, will Government include in the agenda for the next week or the week after a discussion on the reports of

[Shri Amrit Nahata]

the ARC. I had written a letter to you and the BAC signed by about 60 members. In the last meeting of the Committee, you put it for discussion and the Secretary was very legitimately wanting to know what specific reports of the Commission I wanted to be discussed. I have already written to you that the most important and the most crucial report of the ARC is the report on personnel administration. So, I would now request the Minister of Parliamentary Affairs to agree to a debate on that particular report of the ARC, because, as you and the entire House realise, unless there are basic, drastic and radical changes, nothing can be done.

13 hrs.

Secondly, we have genuine apprehensions that session after session important debates are left to be taken up at the fag end, and sometimes they never come up for discussion. So, I would request him not to put off the debate on the Fourth Plan any more, and have this debate as early as possible.

Lastly, we always discuss internal affairs piecemeal. Would not Government come forward with a proposal to have a regular debate on foreign affairs?

MR. SPEAKER: I think we should have a regular debate on foreign affairs. Now it is getting unnecessarily delayed.

श्री प्रताप सिंह (शिमला) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक ही पायंट रेज करना चाहता हूं। होम मिनिस्टर, श्री पन्त, ने इस हाउस में यह घोषणा की थी कि अगले हफ्ते हिमाचल प्रदेश को स्टेटहुड देने के बारे में बिल लाया जायेगा और उन्होंने यह भी विश्वास दिलाया था कि उसको पास कर दिया जायेगा। आज इस सेशन के तीसरे हफ्ते के बिजिनेस की घोषणा की गई है, लेकिन मुझे अफसोस है कि मंत्री महोदय ने उस बिल के बारे में जिक्र तक भी नहीं किया है कि अगले हफ्ते वह बिल आ रहा है, या उस पर विचार हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि वह यह घोषणा करेंगे कि आने वाले हफ्ते में हिमाचल प्रदेश को पूरी स्टेट का दर्जा देने के बारे में बिल लाया जायेगा और उसको पास कर दिया जायेगा।

MR. SPEAKER: I am not going to allow this type of discussion in future if you go on making a regular speech on it.

श्री प्रताप सिंह: अध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से इस हाउस में यह वादा किया गया था कि मौजूदा सेशन में वह बिल पास कर दिया जायेगा।

श्री विभूति मिश्र (मोतीहारी) : अध्यक्ष महोदय, हमारे सदन का यह नियम बना हुआ है कि नान-आफिशल बिल लैप्स नहीं करता है, लेकिन अगर नान-आफिशल रेजोल्यूशन न आ सके, तो वह लैप्स हो जाता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नान-आफिशल बिल की तरह नान-आफिशल रेजोल्यूशन भी लैप्स नहीं होना चाहिए और उन दोनों में कोई फर्क नहीं होना चाहिए।

देश में बेकारी की समस्या बड़ी गम्भीर हो रही है। बेकारी के कारण बंगाल में जो हालत पैदा हो गई है, उसको आप देख ही रहे हैं। बिहार की भी यही हालत है। बिहार के चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि नक्सलाइट्स को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। इस लिए मेरा निवेदन है कि सरकार अनएम्प्लायमेंट के बारे में इस हाउस में टिसकशन कराये।

नार्थ बिहार के डेवेलपमेंट के बारे में सरकार को एक स्मृतिपत्र दिया गया है, लेकिन आज तक यह पता नहीं चला है कि उसके बारे में क्या किया गया है। बरौनी के फर्टलाइजर कारखाने का काम रुका पड़ा है। उसको चलाने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

श्री मु० अ० खां (कासगंज) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार की तवज्जुह एक बड़े सीरियस मैटर की तरफ दिलाना

चाहता हूं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में बिल को सरकार ने बीच में लटका रखा है, जिसका नतीजा यह है कि अलीगढ़ में कम्युनल एलिमेंट्स बहुत सिर उठा रहे हैं। वहां मुसलमानों के खिलाफ पैम्फलेट्स निकाले गये हैं, जिनमें मुसलमानों को खुल कर गालियां दी गई हैं। मेरे पास ऐसे दो पैम्फलेट्स हैं। इस वक्त वे मेरे पास नहीं हैं। अगर आप चाहेंगे, तो मैं आपके सामने रख दूंगा। मुसलमानों को सड़कों पर चलने नहीं दिया जाता है। उनको मारा जाता है और उनकी साइकलों को छीना जा रहा है। कम्युनल एलिमेंट्स अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के असल मकसद को खत्म करना चाहते हैं। अगर सरकार ने इस बारे में जल्दी फैसला न किया, तो वहां पर कम्युनल बलवा हो जायेगा, जिसको वह दबा नहीं पायेगी। क्या सरकार इस सेशन में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में एक काम्प्रिहेंसिव बिल ला रही है या नहीं, ताकि मौजूदा पोजीशन खत्म हो? अगर वहां पर बलवा हो गया, तो हजारों आदमी मारे जायेंगे। क्या सरकार उस बिल को पार्लियामेंट में लाने के लिये तैयार है या नहीं?

SHRI S. R. DAMANI (Sholapur): There is an acute shortage of cotton. Last week four mills in West Bengal had closed down. The hon. Minister promised to do something to ease the shortage but nothing is being done. Thousands of workers will go out of employment and the economy of many small cities is going to be disrupted. The hon. Minister for foreign trade should make a statement about the import policy of cotton so that these mills do not close down.

श्री देवराव पाटिल (यवतमाल) : अध्यक्ष महोदय, देश में कई राज्यों में अतिवृष्टि के कारण कृषि-उपज को बहुत क्षति पहुंची है। उसके दो परिणाम हुए हैं एक तो हर एक प्रान्त में अनाज की भारी कमी हो रही है और दूसरे, उसके कारण ग्रामीण बेंकारी बढ़ रही है। और उसकी समस्या बड़ी गम्भीर हो रही है। इसलिये मैंने यह सुझाव दिया है कि इस विषय पर इस सदन में चर्चा हो। मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि वह अगले सप्ताह उसके बारे में प्रयत्न करें।

SHRI SONAVANE (Pandharpur) : I want a discussion on the soaring prices of consumer goods because it entails a lot of strain on a normal household.

SHRI K. RAGHU RAMAIAH : Various valuable suggestions and recommendations have been made by various sections of the House. Serious apprehensions have been expressed in respect of certain matters...*(Interruption)* I shall convey them to the Ministers concerned.

In regard to price situation, I think there is a non-official resolution in the name of Shri Indrajit Gupta.

SHRI RABI RAY : We want a discussion out of Government's time.

SHRI RAGHU RAMAIAH : Whatever feelings have been expressed will be literally, correctly and truthfully conveyed by me to the Ministers concerned.

13.07 hrs.

STATEMENT RE : DISMISSAL OF A LECTURER OF SALWAN COLLEGE, DELHI

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : अध्यक्ष महोदय आइटम 9 के बारे में—डा० राव के स्टेटमेंट पर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

मुझे खुशी है कि आज मंत्री महोदय यह वक्तव्य दे रहे हैं, लेकिन मेरी आपत्ति इस प्रकार है। इस सदन में कई दफा यह निश्चित किया गया है कि नियम 372 के अन्तर्गत कोई मंत्री स्वयं कभी भी कोई वक्तव्य दे सकता है और सदस्य उसके बारे में सवाल नही पूछ सकते हैं, लेकिन अगर किसी सवाल के बारे में सदस्यों के द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आदि के नोटिस